

EXAM GENIUS

Presents

WEEKLY GENIUS BANKING AND FINANCE

In BILINGUAL

24 - 30 MAY 2026

India's No. 1 Platform for UPSC
| SSC | BANK RAILWAY Exam



 UPSC

 SSC

 BANK

 RAILWAY

 STATE EXAMS

Ques: Emirates NBD launched an open offer to acquire what percentage stake in RBL Bank?

प्रश्न: एमिरेट्स एनबीडी ने आरबीएल बैंक में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदने के लिए ओपन ऑफर लॉन्च किया है?

- A) 15%
- B) 20%
- C) 26%
- D) 30%
- E) 49%

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

- Emirates NBD Bank announced an open offer to acquire up to 26% stake in RBL Bank.
- एमिरेट्स एनबीडी बैंक ने आरबीएल बैंक में 26% हिस्सेदारी खरीदने के लिए ओपन ऑफर की घोषणा की।
- The bank plans to acquire 415.59 million equity shares of RBL Bank.
- बैंक आरबीएल बैंक के 415.59 मिलियन इक्विटी शेयर खरीदने की योजना बना रहा है।
- The offer price has been fixed at ₹282.38 per equity share.
- प्रति इक्विटी शेयर ऑफर मूल्य ₹282.38 निर्धारित किया गया है।
- The total acquisition value is estimated at around ₹11,735 crore.
- इस अधिग्रहण का कुल मूल्य लगभग ₹11,735 करोड़ आंका गया है।
- The acquisition will be completed entirely through cash payment.
- यह अधिग्रहण पूरी तरह नकद भुगतान के माध्यम से किया जाएगा।
- Emirates NBD has received all necessary regulatory and government approvals for the deal.
- एमिरेट्स एनबीडी को इस सौदे के लिए सभी आवश्यक नियामकीय और सरकारी मंजूरियां प्राप्त हो चुकी हैं।
- The investment of around \$3 billion is considered one of the largest equity fund raises in the Indian banking sector.

- लगभग 3 बिलियन डॉलर का यह निवेश भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में सबसे बड़े इक्विटी फंड जुटाव में से एक माना जा रहा है।
- It is also the first acquisition of a majority stake in a profitable Indian bank by a foreign banking institution.
- यह किसी विदेशी बैंकिंग संस्था द्वारा लाभकारी भारतीय बैंक में बहुमत हिस्सेदारी का पहला अधिग्रहण है।

Static Part | स्थैतिक जानकारी:

- Emirates NBD Foundation Year – 1963
- एमिरेट्स एनबीडी की स्थापना – 1963
- Headquarters – Dubai, UAE
- मुख्यालय – दुबई, यूएई
- CEO – Shayne Nelson
- सीईओ – Shayne Nelson
- RBL Bank Foundation Year – 1943
- आरबीएल बैंक की स्थापना – 1943
- Headquarters – Mumbai
- मुख्यालय – मुंबई
- MD & CEO – R. Subramaniakumar
- एमडी एवं सीईओ – आर. सुब्रमणियाकुमार
- Tagline – Apno Ka Bank
- टैगलाइन – Apno Ka Bank



Ques: RAINMUMBAI, India's first exchange-traded weather derivatives contract, has been launched by which organization?

प्रश्न: भारत का पहला एक्सचेंज-ट्रेडेड वेदर डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट RAINMUMBAI किस संगठन द्वारा लॉन्च किया गया है?

- A) NSE / एनएसई
- B) BSE / बीएसई
- C) NCDEX / एनसीडीईएक्स

- D) RBI / आरबीआई
- E) NABARD / नाबार्ड

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

- The National Commodity and Derivatives Exchange (NCDEX) will launch RAINMUMBAI on May 29, 2026.
- नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज (NCDEX) 29 मई 2026 को RAINMUMBAI लॉन्च करेगा।
- RAINMUMBAI is India's first exchange-traded weather derivatives contract.
- RAINMUMBAI भारत का पहला एक्सचेंज-ट्रेडेड वेदर डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है।
- The contract has received approval from the Securities and Exchange Board of India (SEBI).
- इस कॉन्ट्रैक्ट को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) से मंजूरी प्राप्त हुई है।
- The product has been developed in collaboration with IIT Bombay.
- इस उत्पाद को IIT बॉम्बे के सहयोग से विकसित किया गया है।
- Rainfall data from the India Meteorological Department (IMD) will be used for the contract.
- इस कॉन्ट्रैक्ट में भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के वर्षा आंकड़ों का उपयोग किया जाएगा।
- The instrument aims to help businesses and farmers hedge against monsoon variability and weather-related losses.
- यह साधन व्यवसायों और किसानों को मानसून की अनिश्चितता एवं मौसम से होने वाले नुकसान से सुरक्षा प्रदान करेगा।
- IMD weather stations at Santacruz and Colaba in Mumbai will provide rainfall observations.
- मुंबई के सांताक्रूज़ और कोलाबा स्थित IMD मौसम केंद्र वर्षा संबंधी आंकड़े उपलब्ध कराएंगे।

Static Part | स्थैतिक जानकारी:

- Organization – NCDEX (National Commodity and Derivatives Exchange)

- संगठन – NCDEX (नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज)
 - NCDEX Established – 2003
 - NCDEX की स्थापना – 2003
 - NCDEX Headquarters – Mumbai
 - NCDEX मुख्यालय – Mumbai
 - Managing Director & CEO – Arun Raste
 - प्रबंध निदेशक एवं CEO – Arun Raste
-

Ques: The Government of India increased stake dilution in which bank up to 8% through OFS?

प्रश्न: भारत सरकार ने किस बैंक में OFS के माध्यम से हिस्सेदारी बिक्री को 8% तक बढ़ाया है?

- A) Punjab National Bank / पंजाब नेशनल बैंक
- B) Bank of Baroda / बैंक ऑफ बड़ौदा
- C) Central Bank of India / सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
- D) Indian Bank / इंडियन बैंक
- E) Canara Bank / केनरा बैंक

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

- The Government of India increased stake dilution in Central Bank of India up to 8% through Offer for Sale (OFS).
- भारत सरकार ने ऑफर फॉर सेल (OFS) के माध्यम से सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में हिस्सेदारी बिक्री को 8% तक बढ़ाया।
- The OFS received strong institutional investor demand and was oversubscribed 2.35 times on Day 1.
- OFS को संस्थागत निवेशकों से मजबूत मांग मिली और पहले दिन यह 2.35 गुना सब्सक्राइब हुआ।

- The Centre exercised the entire greenshoe option due to high investor response.
- निवेशकों की अधिक रुचि के कारण केंद्र सरकार ने पूरा ग्रीनशू विकल्प लागू किया।
- The government aims to raise around ₹2,456 crore through the stake sale.
- सरकार का लक्ष्य इस हिस्सेदारी बिक्री के माध्यम से लगभग ₹2,456 करोड़ जुटाना है।
- The OFS is intended to help the bank comply with SEBI's minimum public shareholding norm of 25%.
- यह OFS बैंक को सेबी के 25% न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता नियम का पालन कराने के उद्देश्य से किया गया है।
- After the stake sale, the government's holding in Central Bank of India will reduce from 89.27% to around 81.27%.
- हिस्सेदारी बिक्री के बाद सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में सरकार की हिस्सेदारी 89.27% से घटकर लगभग 81.27% रह जाएगी।
- The floor price for the OFS was fixed at ₹31 per share.
- OFS के लिए न्यूनतम मूल्य ₹31 प्रति शेयर निर्धारित किया गया।

Static Part | स्थैतिक जानकारी:

- Central Bank of India Foundation Year – 1911
- सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया स्थापना वर्ष – 1911
- Headquarters – Mumbai
- मुख्यालय – मुंबई
- MD & CEO – Shri Kalyan Kumar
- एमडी एवं सीईओ – श्री कल्याण कुमार
- Tagline – Central to you since 1911
- टैगलाइन – Central to you since 1911

Ques: What was the growth rate recorded by India's eight core infrastructure sectors in April 2026?

प्रश्न: अप्रैल 2026 में भारत के आठ प्रमुख अवसंरचना क्षेत्रों ने कितनी वृद्धि दर्ज की?

- A) 1.7%
- B) 2.5%

- C) 3.2%
- D) 4.1%
- E) 5.0%

Answer: Option A

Explanation | व्याख्या:

- India's eight core infrastructure sectors recorded 1.7% growth in April 2026.
 - भारत के आठ प्रमुख अवसंरचना क्षेत्रों ने अप्रैल 2026 में 1.7% की वृद्धि दर्ज की।
 - The data was released by the Ministry of Commerce and Industry.
 - यह आंकड़े वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी किए गए।
 - Among the core sectors, Cement, Steel, and Electricity registered positive growth.
 - प्रमुख क्षेत्रों में सीमेंट, इस्पात और बिजली उत्पादन ने सकारात्मक वृद्धि दर्ज की।
 - The eight core industries include Coal, Crude Oil, Natural Gas, Refinery Products, Fertilizers, Steel, Cement, and Electricity.
 - आठ प्रमुख उद्योगों में कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट और बिजली शामिल हैं।
 - These industries are considered crucial indicators of industrial and economic activity in India.
 - इन उद्योगों को भारत की औद्योगिक और आर्थिक गतिविधियों का महत्वपूर्ण संकेतक माना जाता है।
 - The eight core industries together account for 40.27% weight in the Index of Industrial Production (IIP).
 - ये आठ प्रमुख उद्योग मिलकर Index of Industrial Production (IIP) में 40.27% भार रखते हैं।
-

Ques: For which financial year did RBI approve a record surplus transfer of Rs. 2.87 lakh crore to the Central Government?

प्रश्न: RBI ने केंद्र सरकार को 2.87 लाख करोड़ रुपये के रिकॉर्ड अधिशेष हस्तांतरण को किस वित्त वर्ष के लिए मंजूरी दी?

- A) FY 2023-24 / वित्त वर्ष 2023-24
- B) FY 2024-25 / वित्त वर्ष 2024-25
- C) FY 2025-26 / वित्त वर्ष 2025-26
- D) FY 2026-27 / वित्त वर्ष 2026-27
- E) FY 2022-23 / वित्त वर्ष 2022-23

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

- The Reserve Bank of India (RBI) approved a surplus transfer of Rs. 2.87 lakh crore to the Central Government for FY 2025-26.
- भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र सरकार को 2.87 लाख करोड़ रुपये के अधिशेष हस्तांतरण को मंजूरी दी।
- The total surplus transferred amounts to Rs. 2,86,588.46 crore.
- कुल अधिशेष हस्तांतरण राशि 2,86,588.46 करोड़ रुपये है।
- The dividend amount is around 6.7% higher than the Rs. 2.69 lakh crore transferred in FY25.
- यह लाभांश राशि FY25 में हस्तांतरित 2.69 लाख करोड़ रुपये की तुलना में लगभग 6.7% अधिक है।
- RBI's gross income increased by 26.42% year-on-year to Rs. 3.96 lakh crore.
- RBI की सकल आय वर्ष-दर-वर्ष 26.42% बढ़कर 3.96 लाख करोड़ रुपये हो गई।
- The balance sheet of RBI expanded by 20.61% to Rs. 91.97 lakh crore.
- RBI की बैलेंस शीट 20.61% बढ़कर 91.97 लाख करोड़ रुपये हो गई।
- The surplus transfer strengthens the government's fiscal position and supports public expenditure.
- यह अधिशेष हस्तांतरण सरकार की राजकोषीय स्थिति को मजबूत करता है और सार्वजनिक व्यय को समर्थन देता है।

Static Part | स्थैतिक जानकारी:

- RBI Established – 1 April 1935

- RBI की स्थापना – 1 अप्रैल 1935
- Headquarters – Mumbai
- मुख्यालय – मुंबई
- Governor – Sanjay Malhotra
- गवर्नर – संजय मल्होत्रा
- Nationalised – 1 January 1949
- राष्ट्रीयकरण – 1 जनवरी 1949

Ques: According to the latest UN report, India's revised GDP growth forecast for 2026 is what percentage?

प्रश्न: नवीनतम संयुक्त राष्ट्र रिपोर्ट के अनुसार 2026 के लिए भारत की संशोधित GDP वृद्धि rate कितनी है?

- A) 5.8%
- B) 6.0%
- C) 6.4%
- D) 6.6%
- E) 7.0%

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

- The United Nations revised India's 2026 economic growth forecast downward to 6.4% from 6.6%.
- संयुक्त राष्ट्र ने भारत की 2026 आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान 6.6% से घटाकर 6.4% कर दिया है।
- The downgrade was announced in a report released by UN DESA (United Nations Department of Economic and Social Affairs).
- यह कटौती UN DESA (संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक मामलों का विभाग) की रिपोर्ट में की गई है।
- The revision was due to global uncertainties and economic shocks arising from the ongoing West Asia crisis.

- यह संशोधन वैश्विक अनिश्चितताओं और पश्चिम एशिया संकट से उत्पन्न आर्थिक झटकों के कारण किया गया है।
- Despite the cut, India remains one of the fastest-growing major economies in the world.
- कटौती के बावजूद भारत दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में बना हुआ है।
- The report stated that the West Asia crisis has slowed global growth and increased inflationary pressures.
- रिपोर्ट के अनुसार पश्चिम एशिया संकट ने वैश्विक विकास को धीमा किया है और मुद्रास्फीति के दबाव को बढ़ाया है।

Static Part | स्थैतिक जानकारी:

- UN Full Form – United Nations
- UN का पूर्ण रूप – संयुक्त राष्ट्र
- UN Founded Day – 24 October 1945
- संयुक्त राष्ट्र स्थापना दिवस – 24 अक्टूबर 1945
- UN Headquarters – New York, USA
- संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय – न्यूयॉर्क, अमेरिका
- UN Secretary-General – António Guterres
- संयुक्त राष्ट्र महासचिव – António Guterres

Ques: Which two institutions signed an MoU to strengthen corporate governance, ESG, and capital market development in India?

प्रश्न: भारत में कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ESG और पूंजी बाजार विकास को मजबूत करने हेतु किन दो संस्थानों ने MoU पर हस्ताक्षर किए?

- A) RBI and SEBI / RBI और SEBI
- B) NISM and IICA / NISM और IICA
- C) NABARD and SIDBI / NABARD और SIDBI
- D) NSE and BSE / NSE और BSE

E) IIM Ahmedabad and NITI Aayog / IIM अहमदाबाद और नीति आयोग

Answer: Option B

Explanation | व्याख्या:

- National Institute of Securities Markets (NISM) and Indian Institute of Corporate Affairs (IICA) signed a Memorandum of Understanding (MoU).
- National Institute of Securities Markets (NISM) और Indian Institute of Corporate Affairs (IICA) ने एक Memorandum of Understanding (MoU) पर हस्ताक्षर किए।
- The partnership aims to strengthen corporate governance, ESG, and capital market development in India.
- इस साझेदारी का उद्देश्य भारत में कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ESG और पूंजी बाजार विकास को मजबूत करना है।
- NISM was established by SEBI, while IICA functions under the Ministry of Corporate Affairs.
- NISM की स्थापना SEBI द्वारा की गई थी, जबकि IICA, Ministry of Corporate Affairs के अंतर्गत कार्य करता है।
- Under the collaboration, both institutions will jointly conduct capacity building programmes and certification courses.
- इस सहयोग के तहत दोनों संस्थान संयुक्त रूप से क्षमता निर्माण कार्यक्रम और प्रमाणन पाठ्यक्रम संचालित करेंगे।
- They will also develop executive education modules and training programmes.
- वे कार्यकारी शिक्षा मॉड्यूल और प्रशिक्षण कार्यक्रम भी विकसित करेंगे।
- The programmes are aimed at SEBI officers, regulatory officials, and financial sector professionals.
- ये कार्यक्रम SEBI अधिकारियों, नियामक अधिकारियों और वित्तीय क्षेत्र के पेशेवरों के लिए होंगे।
- ESG refers to Environmental, Social, and Governance standards used to evaluate sustainable business practices.
- ESG का अर्थ Environmental, Social, and Governance है, जिसका उपयोग सतत

व्यावसायिक प्रथाओं के मूल्यांकन के लिए किया जाता है।

Static Part | स्थैतिक जानकारी:

- NISM Full Form – National Institute of Securities Markets
- NISM का पूर्ण रूप – National Institute of Securities Markets
- NISM Established – 2006
- NISM की स्थापना – 2006
- NISM Headquarters – Mumbai, Maharashtra
- NISM मुख्यालय – मुंबई, महाराष्ट्र
- IICA Full Form – Indian Institute of Corporate Affairs
- IICA का पूर्ण रूप – Indian Institute of Corporate Affairs
- IICA Formed – 2008
- IICA की स्थापना – 2008
- IICA Headquarters – Gurugram, Haryana
- IICA मुख्यालय – गुरुग्राम, हरियाणा

Ques: Net FDI into India increased to how much in FY26 according to RBI data?

प्रश्न: RBI के अनुसार FY26 में भारत में शुद्ध FDI बढ़कर कितना हो गया?

- A) \$3.40 billion / 3.40 बिलियन डॉलर
- B) \$5.20 billion / 5.20 बिलियन डॉलर
- C) \$7.65 billion / 7.65 बिलियन डॉलर
- D) \$10.12 billion / 10.12 बिलियन डॉलर
- E) \$40.95 billion / 40.95 बिलियन डॉलर

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

- Net foreign direct investment (FDI) into India rose sharply to \$7.65 billion in FY26.
- भारत में शुद्ध प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) FY26 में बढ़कर 7.65 बिलियन डॉलर हो गया।
- Net FDI had stood at \$959 million in FY25.
- FY25 में शुद्ध FDI 959 मिलियन डॉलर था।
- March marked the second consecutive month of positive net inflows at \$1.57 billion.
- मार्च लगातार दूसरा महीना रहा जब शुद्ध प्रवाह सकारात्मक रहा और यह 1.57 बिलियन डॉलर दर्ज किया गया।
- Net FDI had turned positive in February after remaining negative for six consecutive months.
- लगातार छह महीनों तक नकारात्मक रहने के after फरवरी में शुद्ध FDI सकारात्मक हुआ।
- Net inflows stood at \$4.44 billion in February.
- फरवरी में शुद्ध निवेश प्रवाह 4.44 बिलियन डॉलर रहा।
- Gross inward FDI into India increased to \$40.95 billion in FY26.
- FY26 में भारत में सकल inward FDI बढ़कर 40.95 बिलियन डॉलर हो गया।
- Equity inflows rose to \$62.28 billion during the year.
- वर्ष के दौरान इक्विटी निवेश बढ़कर 62.28 बिलियन डॉलर हो गया।
- Reinvested earnings increased to \$25.56 billion.
- पुनर्निवेशित आय बढ़कर 25.56 बिलियन डॉलर हो गई।
- Direct investment abroad by Indian firms rose to \$33.29 billion.
- भारतीय कंपनियों द्वारा विदेशों में प्रत्यक्ष निवेश बढ़कर 33.29 बिलियन डॉलर हो गया।

Static Part | स्थैतिक जानकारी:

- FDI Full Form – Foreign Direct Investment
- FDI का पूर्ण रूप – Foreign Direct Investment
- RBI Headquarters – Mumbai
- RBI मुख्यालय – मुंबई
- RBI Governor – Sanjay Malhotra
- RBI गवर्नर – संजय मल्होत्रा

- Finance Minister – Nirmala Sitharaman
- वित्त मंत्री – निर्मला सीतारमण

Ques: Why did the Reserve Bank of India (RBI) impose a monetary penalty on City Union Bank?

प्रश्न: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने City Union Bank पर मौद्रिक जुर्माना क्यों लगाया?

- A) Failure to maintain CRR / CRR बनाए रखने में विफलता
- B) Violation of foreign exchange rules / विदेशी मुद्रा नियमों का उल्लंघन
- C) Levying charges on certain agricultural loans and failure to report SHG data / कुछ कृषि ऋणों पर शुल्क लगाने और SHG डेटा रिपोर्ट न करने के कारण
- D) Cybersecurity breach / साइबर सुरक्षा उल्लंघन
- E) Delay in ATM services / एटीएम सेवाओं में देरी

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

- The Reserve Bank of India (RBI) imposed monetary penalties on City Union Bank, Mintifi Finserve, and Newa Investments for regulatory violations.
- भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने नियामकीय उल्लंघनों के कारण City Union Bank, Mintifi Finserve और Newa Investments पर मौद्रिक जुर्माना लगाया।
- City Union Bank was fined ₹10.10 lakh.
- City Union Bank पर ₹10.10 लाख का जुर्माना लगाया गया।
- The bank levied loan-related charges on certain agricultural loans up to ₹25,000 that qualified under Priority Sector Lending (PSL).
- बैंक ने Priority Sector Lending (PSL) के अंतर्गत आने वाले ₹25,000 तक के कुछ कृषि ऋणों पर ऋण-संबंधी शुल्क लगाया।
- The bank also failed to report Self-Help Group (SHG) member-level data to credit information companies.
- बैंक SHG सदस्यों के स्तर का डेटा क्रेडिट सूचना कंपनियों को रिपोर्ट करने में भी विफल

रहा।

- RBI imposed a penalty of ₹3.10 lakh on Mintifi Finserve for not uploading KYC records to the Central KYC Records Registry within the prescribed timeline.
- RBI ने Mintifi Finserve पर निर्धारित समयसीमा के भीतर Central KYC Records Registry में KYC रिकॉर्ड अपलोड न करने के कारण ₹3.10 लाख का जुर्माना लगाया।
- Newa Investments was fined ₹2.70 lakh for appointing directors without prior written approval from RBI.
- Newa Investments पर RBI की पूर्व लिखित अनुमति के बिना निदेशकों की नियुक्ति करने के कारण ₹2.70 लाख का जुर्माना लगाया गया।
- RBI imposes penalties to ensure compliance with banking and financial regulations.
- RBI बैंकिंग और वित्तीय नियमों के पालन को सुनिश्चित करने के लिए जुर्माना लगाता है।

Ques: How much final dividend per equity share was declared by LIC for FY26?

प्रश्न: FY26 के लिए LIC ने प्रति इक्विटी शेयर कितना अंतिम लाभांश घोषित किया?

- A) ₹5
- B) ₹8
- C) ₹10
- D) ₹12
- E) ₹15

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

- Life Insurance Corporation of India (LIC) reported over 23% year-on-year growth in Q4 net profit.
- भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) ने चौथी तिमाही के शुद्ध लाभ में वर्ष-दर-वर्ष 23% से अधिक वृद्धि दर्ज की।
- LIC's consolidated net profit rose to ₹23,467 crore in Q4 FY26.

- Q4 FY26 में LIC का समेकित शुद्ध लाभ बढ़कर ₹23,467 करोड़ हो गया।
- The net profit stood at ₹19,039 crore in the same quarter of the previous year.
- पिछले वर्ष की समान तिमाही में शुद्ध लाभ ₹19,039 करोड़ था।
- LIC's standalone net profit climbed to ₹23,420.43 crore in the March-ended quarter.
- मार्च तिमाही में LIC का स्टैंडअलोन शुद्ध लाभ बढ़कर ₹23,420.43 करोड़ हो गया।
- Total income increased by over 14% to ₹2,76,827.17 crore.
- कुल आय 14% से अधिक बढ़कर ₹2,76,827.17 करोड़ हो गई।
- Net premium income stood at ₹1,64,691.21 crore during the quarter.
- तिमाही के दौरान शुद्ध प्रीमियम आय ₹1,64,691.21 करोड़ रही।
- Income from investments increased to ₹1,09,022.04 crore.
- निवेश से आय बढ़कर ₹1,09,022.04 करोड़ हो गई।
- LIC declared a final dividend of ₹10 per equity share.
- LIC ने प्रति इक्विटी शेयर ₹10 के अंतिम लाभांश की घोषणा की।

Static Part | स्थैतिक जानकारी:

- LIC Established – 1 September 1956
- LIC की स्थापना – 1 सितंबर 1956
- Headquarters – Mumbai
- मुख्यालय – मुंबई
- Chairperson & MD – R. Doraiswamy
- चेयरपर्सन एवं एमडी – आर. डोराइस्वामी
- Tagline – “Yogakshemam Vahamyaham”
- टैगलाइन – “योगक्षेमं वहाम्यहम्”

Ques: Which organisation has been selected as the fund manager for the ₹20,000-crore Maritime Investment Fund (MIF)?

प्रश्न: ₹20,000 करोड़ के Maritime Investment Fund (MIF) के फंड मैनेजर के रूप में किस संगठन का चयन किया गया है?

A) LIC Housing Finance / एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस

- B) SBI Ventures / एसबीआई वेंचर्स
- C) NABARD / नाबार्ड
- D) SIDBI / सिडबी
- E) IFCI / आईएफसीआई

Answer: Option B

Explanation | व्याख्या:

- The Government of India selected SBI Ventures as the fund manager for the ₹20,000-crore Maritime Investment Fund (MIF).
- भारत सरकार ने ₹20,000 करोड़ के Maritime Investment Fund (MIF) के फंड मैनेजर के रूप में SBI Ventures का चयन किया।
- The fund aims to promote investment in India's maritime sector.
- इस फंड का उद्देश्य भारत के समुद्री क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देना है।
- The Maritime Investment Fund is a major component of the ₹25,000-crore Maritime Development Fund approved by the Union Cabinet.
- Maritime Investment Fund, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत ₹25,000 करोड़ के Maritime Development Fund का प्रमुख हिस्सा है।
- The Central Government will contribute ₹9,800 crore, which is 49% of the total corpus.
- केंद्र सरकार कुल कोष का 49% यानी ₹9,800 करोड़ का योगदान देगी।
- The remaining 51% will be mobilised from private investors, sovereign wealth funds, institutional investors, CPSEs, PSUs, and major port authorities.
- शेष 51% राशि निजी निवेशकों, sovereign wealth funds, institutional investors, CPSEs, PSUs और प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरणों से जुटाई जाएगी।
- The fund will follow a blended finance model.
- यह फंड blended finance model के आधार पर संचालित होगा।
- The fund will be registered as a closed-end Category I/II Alternative Investment Fund (AIF) under SEBI.
- यह फंड SEBI के अंतर्गत closed-end Category I/II Alternative Investment Fund (AIF) के रूप में पंजीकृत होगा।

Ques: Who has been appointed as Executive Director for Vertical 2 at CDSL?
प्रश्न: CDSL में वर्टिकल 2 के लिए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है?

- A) Amit Mahajan / अमित महाजन
- B) Nehal Vora / नेहल वोरा
- C) Nayana Ovalekar / नयना ओवलेकर
- D) Tuhin Kanta Pandey / तुहिन कांत पांडेय
- E) Ajay Tyagi / अजय त्यागी

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

- The Securities and Exchange Board of India (SEBI) approved the appointment of two new Executive Directors at CDSL.
- भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने CDSL में दो नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स की नियुक्ति को मंजूरी दी।
- Amit Mahajan was appointed as Executive Director for Vertical 1.
- अमित महाजन को वर्टिकल 1 के लिए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया गया।
- He will oversee critical operations under Vertical 1.
- वे वर्टिकल 1 के अंतर्गत महत्वपूर्ण संचालन कार्यों की देखरेख करेंगे।
- Nayana Ovalekar was appointed as Executive Director for Vertical 2.
- नयना ओवलेकर को वर्टिकल 2 के लिए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया गया।
- She will handle regulatory, compliance, risk management and investor grievances.
- वे रेगुलेटरी, कंप्लायंस, रिस्क मैनेजमेंट तथा निवेशक शिकायतों की जिम्मेदारी संभालेंगी।
- The appointments will become effective after shareholder ratification and joining formalities.
- ये नियुक्तियाँ शेयरधारकों की मंजूरी और जॉइनिंग प्रक्रिया के बाद प्रभावी होंगी।
- CDSL shares closed at ₹1,217.40 on NSE, up by 1.10%.
- NSE पर CDSL का शेयर ₹1,217.40 पर बंद हुआ, जिसमें 1.10% की बढ़त दर्ज की गई।

Static Part | स्थैतिक जानकारी:

- SEBI Established – 12 April 1992
- SEBI की स्थापना – 12 अप्रैल 1992
- Headquarter – Mumbai
- मुख्यालय – मुंबई
- Chairperson – Tuhin Kanta Pandey
- अध्यक्ष – तुहिन कांत पांडेय
- CDSL Founded – 1999
- CDSL की स्थापना – 1999
- Headquarter – Mumbai
- मुख्यालय – मुंबई
- MD & CEO – Nehal Vora
- MD एवं CEO – नेहल वोरा
- CDSL Full Form – Central Depository Services (India) Limited
- CDSL का पूर्ण रूप – सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड

Ques: Under whose chairmanship was the 623rd meeting of the Central Board of Directors of the Reserve Bank of India (RBI) held?

प्रश्न: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के केंद्रीय निदेशक मंडल की 623वीं बैठक किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुई?

- A) Shaktikanta Das / शक्तिकांत दास
- B) Sanjay Malhotra / संजय मल्होत्रा
- C) Ajay Seth / अजय सेठ
- D) T. Rabi Sankar / टी. रबी शंकर
- E) M. Rajeshwar Rao / एम. राजेश्वर राव

Answer: Option B

Explanation | व्याख्या:

- The 623rd meeting of the Central Board of Directors of the Reserve Bank of India (RBI) was held in Mumbai.
- भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के केंद्रीय निदेशक मंडल की 623वीं बैठक मुंबई में आयोजित हुई।
- The meeting was held under the chairmanship of RBI Governor Sanjay Malhotra.
- यह बैठक RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता में आयोजित की गई।
- RBI's gross income increased by 26.42% during Financial Year 2025–26.
- वित्त वर्ष 2025–26 में RBI की सकल आय में 26.42% की वृद्धि हुई।
- Expenditure before risk provisions rose by 27.60% during the same period.
- इसी अवधि में जोखिम प्रावधानों से पूर्व व्यय में 27.60% की वृद्धि हुई।
- Net income before risk provisions and transfer to statutory funds stood at ₹3.95 lakh crore in FY 2025–26.
- जोखिम प्रावधानों और वैधानिक निधियों में हस्तांतरण से पूर्व शुद्ध आय FY 2025–26 में ₹3.95 लाख करोड़ रही।
- In FY 2024–25, the corresponding figure was ₹3.13 lakh crore.
- FY 2024–25 में यह आंकड़ा ₹3.13 लाख करोड़ था।
- RBI's balance sheet expanded by 20.61% to ₹91.97 lakh crore as of March 31, 2026.
- 31 मार्च 2026 तक RBI की बैलेंस शीट 20.61% बढ़कर ₹91.97 लाख करोड़ हो गई।

Ques : What is the new base year for the revised Index of Industrial Production (IIP) series launched by MoSPI?

प्रश्न: MoSPI द्वारा शुरू की गई संशोधित औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) श्रृंखला का नया आधार वर्ष क्या है?

- A) 2015-16
- B) 2018-19
- C) 2020-21
- D) 2022-23
- E) 2023-24

Answer: Option D

Explanation | व्याख्या:

- The Ministry of Statistics and Programme Implementation (MoSPI) will launch a revamped Index of Industrial Production (IIP) series from June 1.
- सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) 1 जून से संशोधित औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) श्रृंखला शुरू करेगा।
- The new IIP series uses 2022-23 as the base year, replacing the old 2011-12 base year.
- नई IIP श्रृंखला में 2022-23 को आधार वर्ष बनाया गया है, जो पुराने 2011-12 आधार वर्ष का स्थान लेगा।
- For the first time, the index will include rare earth minerals and expanded gas supply coverage.
- पहली बार इस सूचकांक में रेयर अर्थ मिनेरल्स और विस्तारित गैस आपूर्ति को शामिल किया गया है।
- The revised series aims to better reflect India's modern industrial and green-energy economy.
- संशोधित श्रृंखला का उद्देश्य भारत की आधुनिक औद्योगिक एवं हरित ऊर्जा अर्थव्यवस्था को बेहतर तरीके से प्रदर्शित करना है।
- The updated item basket includes 1,042 products mapped into 463 item groups.
- अद्यतन आइटम बास्केट में 1,042 उत्पादों को 463 आइटम समूहों में शामिल किया गया है।
- Electricity generation has been divided into renewable and non-renewable categories in the new series.
- नई श्रृंखला में बिजली उत्पादन को नवीकरणीय और गैर-नवीकरणीय श्रेणियों में विभाजित किया गया है।
- The revised IIP series aligns with the National Industrial Classification (NIC-2025).
- संशोधित IIP श्रृंखला को राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण (NIC-2025) के अनुरूप बनाया गया है।

Static Part | स्थैतिक जानकारी:

- Ministry – Ministry of Statistics and Programme Implementation (MoSPI)
- मंत्रालय – सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI)
- Current Union Minister – Rao Inderjit Singh (MoS Independent Charge)
- वर्तमान केंद्रीय मंत्री – राव इंद्रजीत सिंह (स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री)
- Base Year of Old IIP Series – 2011-12
- पुरानी IIP श्रृंखला का आधार वर्ष – 2011-12
- New Base Year of IIP Series – 2022-23
- नई IIP श्रृंखला का आधार वर्ष – 2022-23

Ques: Which FinTech company received approval to operate as a Payment Service Provider (PSP) at GIFT City?

प्रश्न: किस फिनटेक कंपनी को GIFT City में Payment Service Provider (PSP) के रूप में कार्य करने की मंजूरी मिली है?

- A) Razorpay / रेजरपे
- B) Paytm / पेटीएम
- C) Skydo / स्काइडो
- D) Pine Labs / पाइन लैब्स
- E) BharatPe / भारतपे

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

- FinTech company Skydo received approval to operate as a Payment Service Provider (PSP) at GIFT City.
- फिनटेक कंपनी Skydo को GIFT City में Payment Service Provider (PSP) के रूप में कार्य करने की मंजूरी मिली है।
- GIFT City is India's international financial services hub.

- GIFT City भारत का अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र है।
- Skydo will now offer services such as multi-currency payments, international money transfers, global payment collections, and e-money accounts.
- Skydo अब multi-currency payments, international money transfers, global payment collections और e-money accounts जैसी सेवाएँ प्रदान करेगा।
- The company also received RBI approval under the Payment Aggregator-Cross Border (PA-CB) framework for outward international payments.
- कंपनी को outward international payments के लिए RBI से Payment Aggregator-Cross Border (PA-CB) framework के तहत भी मंजूरी मिली है।
- Earlier, Skydo had already received approval for collecting export payments from foreign customers.
- इससे पहले Skydo को विदेशी ग्राहकों से export payments एकत्र करने की अनुमति मिल चुकी थी।
- The approvals strengthen India's digital cross-border payment ecosystem.
- ये मंजूरियाँ भारत के डिजिटल cross-border payment ecosystem को मजबूत करती हैं।

Ques : West Bengal Gramin Bank signed a bancassurance deal with which insurance company?

प्रश्न: पश्चिम बंगाल ग्रामीण बैंक ने किस बीमा कंपनी के साथ बैंकएश्योरेंस समझौता किया?

- A) LIC Housing Finance / एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस
- B) SBI Life Insurance / एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस
- C) HDFC Life Insurance / एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस
- D) Canara HSBC Life Insurance / कैनरा एचएसबीसी लाइफ इंश्योरेंस
- E) ICICI Prudential Life Insurance / आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस

Answer: Option D

Explanation | व्याख्या:

- West Bengal Gramin Bank (WBGB) signed a bancassurance partnership with Canara HSBC Life Insurance.
- पश्चिम बंगाल ग्रामीण बैंक (WBGB) ने कैनरा एचएसबीसी लाइफ इंश्योरेंस के साथ बैंकएश्योरेंस साझेदारी की।
- The partnership aims to provide life, term, and investment insurance products to customers.
- इस साझेदारी का उद्देश्य ग्राहकों को जीवन, टर्म और निवेश बीमा उत्पाद उपलब्ध कराना है।
- Canara HSBC Life Insurance products will be distributed through WBGB's network of 960 branches.
- कैनरा एचएसबीसी लाइफ इंश्योरेंस के उत्पाद WBGB की 960 शाखाओं के माध्यम से वितरित किए जाएंगे।
- The initiative focuses on expanding insurance coverage in rural and semi-urban areas of West Bengal.
- यह पहल पश्चिम बंगाल के ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में बीमा कवरेज बढ़ाने पर केंद्रित है।
- The agreement will improve financial inclusion and insurance accessibility for customers.
- यह समझौता ग्राहकों के लिए वित्तीय समावेशन और बीमा सेवाओं की पहुंच को बेहतर बनाएगा।

Static Part | स्थैतिक जानकारी:

- West Bengal Gramin Bank Headquarters – Murshidabad, West Bengal
- पश्चिम बंगाल ग्रामीण बैंक मुख्यालय – मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल
- Canara HSBC Life Insurance Founded – 2008
- कैनरा एचएसबीसी लाइफ इंश्योरेंस स्थापना – 2008
- Headquarters of Canara HSBC Life Insurance – Gurugram, Haryana
- कैनरा एचएसबीसी लाइफ इंश्योरेंस मुख्यालय – गुरुग्राम, हरियाणा
- Tagline of Canara Bank – “Together We Can”
- कैनरा बैंक की टैगलाइन – “Together We Can”

Ques: Which mutual fund house increased its stake in Bandhan Bank to more than 5% of the bank's paid-up share capital?

प्रश्न: किस म्यूचुअल फंड हाउस ने Bandhan Bank में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाकर बैंक की चुकता शेयर पूंजी (paid-up share capital) का 5% से अधिक कर लिया?

- A) HDFC Mutual Fund / एचडीएफसी म्यूचुअल फंड
- B) ICICI Prudential Mutual Fund / आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड
- C) SBI Mutual Fund / एसबीआई म्यूचुअल फंड
- D) Nippon India Mutual Fund / निप्पोन इंडिया म्यूचुअल फंड
- E) Axis Mutual Fund / एक्सिस म्यूचुअल फंड

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

- SBI Mutual Fund increased its stake in Bandhan Bank and now holds more than 5% of the bank's paid-up share capital.
- SBI Mutual Fund ने Bandhan Bank में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई और अब उसके पास बैंक की चुकता शेयर पूंजी (paid-up share capital) का 5% से अधिक हिस्सा है।
- Before the purchase, SBI Mutual Fund held a 4.9378% stake in the bank.
- खरीद से पहले SBI Mutual Fund के पास बैंक में 4.9378% हिस्सेदारी थी।
- SBI Mutual Fund is India's largest mutual fund house by Assets Under Management (AUM).
- SBI Mutual Fund, Assets Under Management (AUM) के आधार पर भारत का सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड हाउस है।
- Paid-up share capital refers to the total value of shares issued by a company and fully paid by shareholders.
- Paid-up share capital का अर्थ कंपनी द्वारा जारी किए गए और शेयरधारकों द्वारा पूरी तरह भुगतान किए गए शेयरों के कुल मूल्य से है।
- Assets Under Management (AUM) refers to the total cumulative investment managed by a mutual fund.
- Assets Under Management (AUM) का अर्थ किसी म्यूचुअल फंड द्वारा प्रबंधित कुल निवेश राशि से है।

- Increasing stake in a bank reflects investor confidence in the institution's future growth potential.
 - किसी बैंक में हिस्सेदारी बढ़ाना उस संस्था की भविष्य की विकास क्षमता में निवेशकों के विश्वास को दर्शाता है।
-

Ques: What was the total inflow into NRI deposit schemes in FY26?

प्रश्न: FY26 में NRI जमा योजनाओं में कुल प्रवाह कितना था?

- A) \$10.41 billion / \$10.41 बिलियन
- B) \$12.75 billion / \$12.75 बिलियन
- C) \$14.41 billion / \$14.41 बिलियन
- D) \$16.16 billion / \$16.16 बिलियन
- E) \$18.25 billion / \$18.25 बिलियन

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

- Inflows into Non-Resident Indian (NRI) deposit schemes moderated to \$14.41 billion in FY26.
- FY26 में अनिवासी भारतीय (NRI) जमा योजनाओं में प्रवाह घटकर \$14.41 बिलियन रह गया।
- In FY25, NRI deposit inflows were \$16.16 billion.
- FY25 में NRI जमा प्रवाह \$16.16 बिलियन था।
- Outstanding NRI deposits stood at \$165.65 billion at the end of March 2026.
- मार्च 2026 के अंत तक कुल NRI जमा \$165.65 बिलियन रहा।
- FCNR(B) deposits recorded inflows of only \$946 million in FY26.
- FY26 में FCNR(B) जमा में केवल \$946 मिलियन का प्रवाह दर्ज किया गया।
- NR(E)RA deposits saw inflows of \$7.94 billion during FY26.
- FY26 के दौरान NR(E)RA जमा में \$7.94 बिलियन का प्रवाह हुआ।
- NRO deposits recorded inflows of \$5.53 billion in FY26.

- FY26 में NRO जमा में \$5.53 बिलियन का प्रवाह दर्ज किया गया।
- The data was released by the Reserve Bank of India (RBI).
- यह आंकड़े भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा जारी किए गए।
- The moderation in inflows was mainly due to weaker demand for FCNR(B) deposits.
- प्रवाह में कमी मुख्य रूप से FCNR(B) जमा की मांग कमजोर होने के कारण हुई।

Static Part | स्थैतिक जानकारी:

- RBI Establishment – 1 April 1935
- RBI की स्थापना – 1 अप्रैल 1935
- Headquarter – Mumbai
- मुख्यालय – मुंबई
- Governor – Sanjay Malhotra
- गवर्नर – संजय मल्होत्रा
- RBI Nationalisation – 1 January 1949
- RBI का राष्ट्रीयकरण – 1 जनवरी 1949
- NRI Full Form – Non-Resident Indian
- NRI का पूर्ण रूप – अनिवासी भारतीय
- FCNR(B) Full Form – Foreign Currency Non-Resident (Bank)
- FCNR(B) का पूर्ण रूप – फॉरेन करेंसी नॉन-रेजिडेंट (बैंक)
- NRO Full Form – Non-Resident Ordinary Account
- NRO का पूर्ण रूप – नॉन-रेजिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट

Genius

Ques: According to Finance Minister Nirmala Sitharaman, what do the “3Fs” refer to?

प्रश्न: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार “3Fs” का क्या अर्थ है?

- A) Food, Farming, Finance / फूड, फार्मिंग, फाइनेंस
- B) Fuel, Fertiliser, Foreign Exchange / ईंधन, उर्वरक, विदेशी मुद्रा
- C) Fuel, Farming, Forex / ईंधन, कृषि, फॉरेक्स
- D) Finance, Fertiliser, Freight / वित्त, उर्वरक, माल परिवहन

E) Food, Fuel, Freight / भोजन, ईंधन, माल परिवहन

Answer: Option B

Explanation | व्याख्या:

- Union Finance Minister Nirmala Sitharaman highlighted “3Fs” — Fuel, Fertiliser and Foreign Exchange — as major external challenges for India’s economy.
- केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने “3Fs” — ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा — को भारत की अर्थव्यवस्था के लिए प्रमुख बाहरी चुनौतियाँ बताया।
- She said the ongoing West Asia crisis is creating uncertainties for businesses and common people.
- उन्होंने कहा कि पश्चिम एशिया संकट व्यवसायों और आम लोगों के for अनिश्चितताएँ पैदा कर रहा है।
- Rising crude oil, fertiliser and gold prices are putting pressure on India’s foreign exchange reserves.
- कच्चे तेल, उर्वरक और सोने की बढ़ती कीमतें भारत के विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव डाल रही हैं।
- Sitharaman stated that delayed cargo movement and higher shipping costs are affecting businesses.
- सीतारमण ने कहा कि कार्गो में देरी और बढ़ती शिपिंग लागत व्यवसायों को प्रभावित कर रही है।
- She emphasized that India’s economic fundamentals remain strong and resilient.
- उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत की आर्थिक बुनियाद मजबूत और लचीली बनी हुई है।
- Petrol prices increased by ₹2.61 per litre and diesel prices by ₹2.71 per litre recently.
- हाल ही में पेट्रोल की कीमत ₹2.61 प्रति लीटर और डीजल की कीमत ₹2.71 प्रति लीटर बढ़ी।
- The Finance Minister appealed against “fear-mongering” and stressed maintaining public confidence.
- वित्त मंत्री ने “भय फैलाने” से बचने की अपील की और जनता का विश्वास बनाए रखने पर जोर दिया।

Static Part | स्थैतिक जानकारी:

- Ministry of Finance Established – 29 October 1946
- वित्त मंत्रालय की स्थापना – 29 अक्टूबर 1946
- Headquarter – New Delhi
- मुख्यालय – नई दिल्ली
- Union Finance Minister – Nirmala Sitharaman
- केंद्रीय वित्त मंत्री – निर्मला सीतारमण
- Foreign Exchange Reserves managed by – RBI
- विदेशी मुद्रा भंडार का प्रबंधन – RBI द्वारा
- RBI Headquarter – Mumbai
- RBI मुख्यालय – मुंबई
- RBI Governor – Sanjay Malhotra
- RBI गवर्नर – संजय मल्होत्रा

Ques: For how many years has RBI approved the re-appointment of Sandeep Bakshi as MD & CEO of ICICI Bank?

प्रश्न: RBI ने संदीप बखशी की ICICI बैंक के MD एवं CEO के रूप में पुनर्नियुक्ति कितने वर्षों के लिए मंजूर की है?

- A) 1 year / 1 वर्ष
- B) 2 years / 2 वर्ष
- C) 3 years / 3 वर्ष
- D) 4 years / 4 वर्ष
- E) 5 years / 5 वर्ष

Answer: Option B

Explanation | व्याख्या:

- The Reserve Bank of India (RBI) approved the re-appointment of Sandeep Bakshi as MD & CEO of ICICI Bank.
- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने संदीप बख्शी की ICICI बैंक के MD एवं CEO के रूप में पुनर्नियुक्ति को मंजूरी दी।
- Sandeep Bakshi has been re-appointed for another two years from October 4, 2026.
- संदीप बख्शी को 4 अक्टूबर 2026 से अगले दो वर्षों के लिए पुनर्नियुक्त किया गया है।
- Following the announcement, ICICI Bank shares rose over 2% on the BSE.
- इस घोषणा के बाद BSE में ICICI बैंक के शेयर 2% से अधिक बढ़ गए।
- ICICI Bank is India's second-largest private sector lender.
- ICICI बैंक भारत का दूसरा सबसे बड़ा निजी क्षेत्र का बैंक है।
- The bank's board had approved Bakshi's re-appointment in January 2026.
- बैंक के बोर्ड ने जनवरी 2026 में बख्शी की पुनर्नियुक्ति को मंजूरी दी थी।
- Under RBI norms, a private sector bank CEO can continue till the age of 70 years.
- RBI के नियमों के अनुसार निजी क्षेत्र के बैंक का CEO 70 वर्ष की आयु तक पद पर रह सकता है।
- Sandeep Bakshi joined the ICICI Group in 1986.
- संदीप बख्शी 1986 में ICICI समूह में शामिल हुए थे।

Static Part | स्थैतिक जानकारी:

- ICICI Bank Founded – 1994
- ICICI बैंक की स्थापना – 1994
- Headquarter – Mumbai
- मुख्यालय – मुंबई
- MD & CEO – Sandeep Bakshi
- एमडी एवं सीईओ – संदीप बख्शी
- Tagline – Hum Hai Na, Khayal Apka
- टैगलाइन – Hum Hai Na, Khayal Apka

Ques: Under which initiative is India Post investing ₹5,800 crore to create fully digital end-to-end postal services?

प्रश्न: पूर्णतः डिजिटल एंड-टू-एंड डाक सेवाएँ विकसित करने के लिए India Post किस पहल के तहत ₹5,800 करोड़ का निवेश कर रहा है?

- A) Digital Bharat Mission / डिजिटल भारत मिशन
- B) Postal Connect Scheme / पोस्टल कनेक्ट योजना
- C) IT 2.0 Initiative / आईटी 2.0 पहल
- D) Smart Communication Programme / स्मार्ट कम्युनिकेशन प्रोग्राम
- E) India Mail Digital Project / इंडिया मेल डिजिटल प्रोजेक्ट

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

- India Post is investing ₹5,800 crore under the IT 2.0 initiative to create fully digital end-to-end postal services.
- India Post पूर्णतः डिजिटल एंड-टू-एंड डाक सेवाएँ विकसित करने के लिए IT 2.0 पहल के तहत ₹5,800 करोड़ का निवेश कर रहा है।
- India Post recorded a revenue of ₹15,373 crore during Financial Year 2025-26.
- वित्तीय वर्ष 2025-26 में India Post ने ₹15,373 करोड़ का राजस्व दर्ज किया।
- This marked one of the strongest financial performances in its 170-year history.
- यह इसके 170 वर्षों के इतिहास में सबसे मजबूत वित्तीय प्रदर्शनों में से एक रहा।
- India Post witnessed a record annual revenue increase of ₹2,100 crore during the financial year.
- इस वित्तीय वर्ष में India Post ने ₹2,100 करोड़ की रिकॉर्ड वार्षिक राजस्व वृद्धि दर्ज की।
- The IT 2.0 initiative aims to modernise postal operations through digital transformation and improved customer services.
- IT 2.0 पहल का उद्देश्य डिजिटल परिवर्तन और बेहतर ग्राहक सेवाओं के माध्यम से डाक संचालन का आधुनिकीकरण करना है।

- India Post plays an important role in delivering postal, financial, and logistics services across the country.
- India Post देशभर में डाक, वित्तीय और लॉजिस्टिक्स सेवाएँ प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

Static Part | स्थैतिक जानकारी:

- India Post Formed – 1 October 1854
- India Post की स्थापना – 1 अक्टूबर 1854
- India Post comes under the Ministry of Communications.
- India Post, संचार मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है।
- India Post Headquarters – New Delhi
- India Post मुख्यालय – नई दिल्ली
- PIN Code System was introduced in India in 1972.
- भारत में PIN Code प्रणाली की शुरुआत 1972 में हुई थी।
- Full Form of PIN – Postal Index Number
- PIN का पूर्ण रूप – पोस्टल इंडेक्स नंबर

Ques : Under which initiative did RBI establish an expert committee on quantum technology?

प्रश्न: आरबीआई ने क्वांटम तकनीक पर विशेषज्ञ समिति किस पहल के तहत गठित की है?

- A) Digital India Mission / डिजिटल इंडिया मिशन
- B) Cyber Suraksha Initiative / साइबर सुरक्षा पहल
- C) Q-SAFE Initiative / Q-SAFE पहल
- D) Quantum Bharat Mission / क्वांटम भारत मिशन
- E) FinSecure India / फिनसिक्योर इंडिया

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

- The Reserve Bank of India (RBI) has constituted an eight-member expert committee under the Q-SAFE initiative.
- भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने Q-SAFE पहल के तहत आठ सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है।
- Q-SAFE stands for Quantum Secure and Adaptive Financial Ecosystem.
- Q-SAFE का पूर्ण रूप Quantum Secure and Adaptive Financial Ecosystem है।
- The committee will study the impact of quantum technology on the financial sector and cyber security systems.
- यह समिति वित्तीय क्षेत्र एवं साइबर सुरक्षा प्रणालियों पर क्वांटम तकनीक के प्रभाव का अध्ययन करेगी।
- Dr. Anil Prabhakar, Professor at IIT Madras, has been appointed as the convener of the committee.
- IIT मद्रास के प्रोफेसर डॉ. अनिल प्रभाकर को समिति का संयोजक नियुक्त किया गया है।
- The committee includes representatives from RBI, SBI, NPCI, MeitY, DST and cybersecurity experts.
- समिति में RBI, SBI, NPCI, MeitY, DST तथा साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों के प्रतिनिधि शामिल हैं।
- The initiative aims to prepare India's financial ecosystem against future quantum-related cyber threats.
- इस पहल का उद्देश्य भारत की वित्तीय प्रणाली को भविष्य के क्वांटम आधारित साइबर खतरों से सुरक्षित बनाना है।
- RBI's FinTech Department will provide secretarial support to the committee.
- आरबीआई का फिनटेक विभाग समिति को सचिवीय सहायता प्रदान करेगा।

Static Part | स्थैतिक जानकारी:

- RBI Established – 1 April 1935
- RBI की स्थापना – 1 अप्रैल 1935
- Headquarter – Mumbai
- मुख्यालय – मुंबई
- Governor – Sanjay Malhotra

- गवर्नर – संजय मल्होत्रा

Ques: Who has been appointed as the chairman of the committee formed by PFRDA to explore the long-term inclusion of new asset classes in pension investments?

प्रश्न: पेंशन निवेश में नए एसेट क्लास के दीर्घकालिक समावेशन की जांच हेतु PFRDA द्वारा गठित समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है?

- A) Sivasubramanian Ramann / शिवसुब्रमणियन रमण
- B) Narayan Ramachandran / नारायण रामचंद्रन
- C) Sanjay Malhotra / संजय मल्होत्रा
- D) Deepak Mohanty / दीपक मोहंती
- E) Amitabh Kant / अमिताभ कांत

Answer: Option B

Explanation | व्याख्या:

- The Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA) formed a committee to explore the long-term inclusion of new asset classes in pension investments.
- पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण (PFRDA) ने पेंशन निवेश में नए एसेट क्लास के दीर्घकालिक समावेशन की जांच के लिए एक समिति गठित की।
- The committee will be chaired by Narayan Ramachandran.
- इस समिति के अध्यक्ष नारायण रामचंद्रन होंगे।
- The objective of the committee is to improve returns for subscribers under the National Pension System (NPS).
- समिति का उद्देश्य National Pension System (NPS) के सब्सक्राइबर्स के लिए बेहतर रिटर्न सुनिश्चित करना है।
- According to the data, the total number of subscribers under NPS reached 2.17 crore in FY26.

- उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार FY26 में NPS के कुल सब्सक्राइबर्स की संख्या 2.17 करोड़ तक पहुँच गई।
- The total pension corpus under NPS increased to around ₹15.95 lakh crore.
- NPS के अंतर्गत कुल पेंशन कॉर्पस बढ़कर लगभग ₹15.95 लाख करोड़ हो गया।
- PFRDA regulates and supervises pension-related activities in India.
- PFRDA भारत में पेंशन संबंधी गतिविधियों का विनियमन और पर्यवेक्षण करता है।

Static Part | स्थैतिक जानकारी:

- PFRDA Full Form – Pension Fund Regulatory and Development Authority
- PFRDA का पूर्ण रूप – पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण
- PFRDA Established – 2003
- PFRDA की स्थापना – 2003
- PFRDA Headquarters – New Delhi
- PFRDA मुख्यालय – नई दिल्ली
- Chairman of PFRDA – Sivasubramanian Ramann
- PFRDA के अध्यक्ष – शिवसुब्रमणियन रमण

Ques : LIC has increased its stake in which public sector bank to 6.06%?

प्रश्न: एलआईसी ने किस सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाकर 6.06% की है?

- A) Punjab National Bank / पंजाब नेशनल बैंक
- B) Bank of Baroda / बैंक ऑफ बड़ौदा
- C) Central Bank of India / सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
- D) Indian Bank / इंडियन बैंक
- E) UCO Bank / यूको बैंक

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

- LIC has increased its stake in Central Bank of India from 3.16% to 6.06%.
- एलआईसी ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में अपनी हिस्सेदारी 3.16% से बढ़ाकर 6.06% कर दी है।
- LIC purchased 26.26 crore shares through market purchase on May 22.
- एलआईसी ने 22 मई को बाजार से 26.26 करोड़ शेयर खरीदे।
- The additional acquisition accounts for 2.901% stake in the bank.
- यह अतिरिक्त खरीद बैंक में 2.901% हिस्सेदारी के बराबर है।
- Central Bank of India informed the stock exchanges about the stake increase.
- सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने स्टॉक एक्सचेंजों को इस हिस्सेदारी वृद्धि की जानकारी दी।
- Shares of Central Bank of India closed at ₹31.29 on BSE.
- बीएसई पर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का शेयर ₹31.29 पर बंद हुआ।
- LIC shares closed 2.93% higher at ₹837.20.
- एलआईसी के शेयर 2.93% बढ़कर ₹837.20 पर बंद हुए।

Static Part | स्थैतिक जानकारी:

- LIC Foundation Year – 1956
- एलआईसी स्थापना वर्ष – 1956
- Headquarters – Mumbai
- मुख्यालय – मुंबई
- CEO and MD of LIC : Shri R. Doraiswamy
- एलआईसी के सीईओ और एमडी: श्री आर. दोरैस्वामी
- Tagline – Yogakshemam Vahamyaham
- टैगलाइन – योगक्षेमं वहाम्यहम्
- Central Bank of India Foundation Year – 1911
- सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया स्थापना वर्ष – 1911
- Headquarters – Mumbai
- मुख्यालय – मुंबई
- MD & CEO – Shri Kalyan Kumar
- एमडी एवं सीईओ – श्री कल्याण कुमार
- Tagline – Central to you since 1911
- टैगलाइन – Central to you since 1911

Ques: Who has been approved by the Reserve Bank of India (RBI) as the part-time Chairman of Federal Bank for a period of three years?

प्रश्न: Reserve Bank of India (RBI) ने Federal Bank के अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में तीन वर्षों के लिए किसकी नियुक्ति को मंजूरी दी है?

- A) KVS Manian / केवीएस मणियन
- B) Elias George / एलियास जॉर्ज
- C) Shyam Srinivasan / श्याम श्रीनिवासन
- D) Rajesh Gopinathan / राजेश गोपीनाथन
- E) Sandeep Bakhshi / संदीप बखशी

Answer: Option B

Explanation | व्याख्या:

- Reserve Bank of India (RBI) approved the appointment of Elias George as the part-time Chairman of Federal Bank for a period of three years.
- भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने एलियास जॉर्ज की Federal Bank के अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में तीन वर्षों के लिए नियुक्ति को मंजूरी दी।
- Elias George has been serving as an independent director on the board of the bank.
- एलियास जॉर्ज बैंक के निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशक के रूप में कार्य कर रहे हैं।
- Federal Bank is one of India's leading private sector banks.
- Federal Bank भारत के प्रमुख निजी क्षेत्र के बैंकों में से एक है।
- The appointment reflects RBI's role in regulating and approving key positions in the banking sector.
- यह नियुक्ति बैंकिंग क्षेत्र में प्रमुख पदों की निगरानी और अनुमोदन में RBI की भूमिका को दर्शाती है।
- Federal Bank continues to expand its banking and digital financial services across India.
- Federal Bank भारतभर में अपनी बैंकिंग और डिजिटल वित्तीय सेवाओं का विस्तार कर रहा है।

Static Part | स्थैतिक जानकारी:

- Federal Bank Founded – 23 April 1931
- Federal Bank की स्थापना – 23 अप्रैल 1931
- Federal Bank Headquarters – Kochi, Kerala
- Federal Bank मुख्यालय – कोच्चि, केरल
- MD & CEO of Federal Bank – KVS Manian
- Federal Bank के MD एवं CEO – केवीएस मणियन
- RBI Established – 1 April 1935
- RBI की स्थापना – 1 अप्रैल 1935
- RBI Headquarters – Mumbai, Maharashtra
- RBI मुख्यालय – मुंबई, महाराष्ट्र
- Kerala Capital – Thiruvananthapuram
- केरल की राजधानी – तिरुवनंतपुरम

Ques : RBI and NPCI are considering linking ATM interchange fees with which index?

प्रश्न: RBI और NPCI एटीएम इंटरचेंज शुल्क को किस सूचकांक से जोड़ने पर विचार कर रहे हैं?

- A) Consumer Price Index (उपभोक्ता मूल्य सूचकांक)
- B) Sensex Index (सेंसेक्स सूचकांक)
- C) Wholesale Price Index (थोक मूल्य सूचकांक)
- D) Repo Rate Index (रेपो रेट सूचकांक)
- E) Industrial Growth Index (औद्योगिक वृद्धि सूचकांक)

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

- The Reserve Bank of India (RBI) and National Payments Corporation of India (NPCI) are considering linking ATM interchange fees with the Wholesale Price Index (WPI).
- भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) और नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) एटीएम इंटरचेंज शुल्क को थोक मूल्य सूचकांक (WPI) से जोड़ने पर विचार कर रहे हैं।
- ATM operators are facing rising operational costs due to higher lease rentals, electricity bills and fuel prices.
- एटीएम ऑपरेटर बढ़े हुए किराये, बिजली बिल और ईंधन कीमतों के कारण बढ़ती परिचालन लागत का सामना कर रहे हैं।
- The ATM interchange fee was fixed at ₹17 in 2021 and later increased to ₹19 in 2025.
- एटीएम इंटरचेंज शुल्क वर्ष 2021 में ₹17 निर्धारित किया गया था, जिसे 2025 में बढ़ाकर ₹19 कर दिया गया।
- RBI and NPCI are also reviewing customer charges of ₹21–₹22 after the free monthly transaction limit is exhausted.
- आरबीआई और NPCI मुफ्त मासिक लेनदेन सीमा समाप्त होने के बाद ₹21–₹22 के ग्राहक शुल्क की भी समीक्षा कर रहे हैं।
- Linking interchange fees with WPI may allow automatic periodic revisions based on inflation trends.
- इंटरचेंज शुल्क को WPI से जोड़ने से मुद्रास्फीति के आधार पर समय-समय पर स्वतः संशोधन संभव हो सकेगा।
- The move aims to ensure sustainability and smooth functioning of ATM networks across the country.
- इस कदम का उद्देश्य देशभर में एटीएम नेटवर्क की स्थिरता और सुचारु संचालन सुनिश्चित करना है।

Static Part | स्थैतिक जानकारी:

- NPCI Established – 2008
- NPCI की स्थापना – 2008
- Headquarter – Mumbai
- मुख्यालय – मुंबई
- MD & CEO – Dilip Asbe
- MD एवं CEO – दिलीप अस्बे

Ques: The Government of India plans to sell up to 2% stake in which company through OFS?

प्रश्न: भारत सरकार OFS के माध्यम से किस कंपनी में 2% तक हिस्सेदारी बेचने की योजना बना रही है?

- A) SBI / एसबीआई
- B) GIC / जीआईसी
- C) LIC / एलआईसी
- D) New India Assurance / न्यू इंडिया एश्योरेंस
- E) NABARD / नाबार्ड

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

- The Government of India plans to divest around 2% stake in Life Insurance Corporation of India (LIC) through an Offer for Sale (OFS).
- भारत सरकार लाइफ इश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (LIC) में लगभग 2% हिस्सेदारी ऑफर फॉर सेल (OFS) के माध्यम से बेचने की योजना बना रही है।
- The proposed stake sale may take place in late June or early July.
- प्रस्तावित हिस्सेदारी बिक्री जून के अंत या जुलाई की शुरुआत में हो सकती है।
- The OFS is mainly aimed at institutional investors.
- यह OFS मुख्य रूप से संस्थागत निवेशकों के लिए लक्षित है।
- The government expects to raise nearly ₹10,000 crore through this divestment.
- सरकार को इस विनिवेश के माध्यम से लगभग ₹10,000 करोड़ जुटाने की उम्मीद है।
- The government currently holds around 96.5% stake in LIC.
- वर्तमान में सरकार की LIC में लगभग 96.5% हिस्सेदारी है।
- LIC has been given time till May 2032 to meet SEBI's 25% minimum public shareholding norms.
- LIC को SEBI के 25% न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता मानदंडों को पूरा करने के लिए मई 2032 तक का समय दिया गया है।
- The proposed OFS is part of the government's broader disinvestment and

market compliance strategy.

- प्रस्तावित OFS सरकार की व्यापक विनिवेश और बाजार अनुपालन रणनीति का हिस्सा है।

Ques: What is the name of the new USD 10 billion financing facility launched by the Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)?

प्रश्न: एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक (AIIB) द्वारा शुरू की गई नई 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर की वित्तीय सुविधा का नाम क्या है?

- A) Energy, Food Security and Economic Resilience Facility (EFSERF) / एनर्जी, फूड सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक रेजिलिएंस फैसिलिटी
- B) Economic Stability Initiative / इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इनिशिएटिव
- C) Global Recovery Fund / ग्लोबल रिकवरी फंड
- D) Sustainable Growth Facility / सस्टेनेबल ग्रोथ फैसिलिटी
- E) Crisis Support Mechanism / क्राइसिस सपोर्ट मैकेनिज्म

Answer: Option A

Explanation | व्याख्या:

- The Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) launched a new USD 10 billion financing facility named the “Energy, Food Security and Economic Resilience Facility (EFSERF).”
- एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक (AIIB) ने “Energy, Food Security and Economic Resilience Facility (EFSERF)” नामक नई 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर की वित्तीय सुविधा शुरू की।
- The facility aims to help member countries tackle the economic impact arising from the ongoing Middle East conflict.
- इस सुविधा का उद्देश्य सदस्य देशों को जारी मध्य-पूर्व संघर्ष से उत्पन्न आर्थिक प्रभावों से निपटने में सहायता करना है।

- AIIB will provide USD 10 billion in financial support over a period of two years.
- AIIB अगले दो वर्षों में 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर की वित्तीय सहायता प्रदान करेगा।
- The initiative focuses on strengthening energy security, food security, and economic resilience among member countries.
- यह पहल सदस्य देशों में ऊर्जा सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा और आर्थिक मजबूती को सुदृढ़ करने पर केंद्रित है।
- AIIB is a multilateral development bank that supports infrastructure and sustainable development projects.
- AIIB एक बहुपक्षीय विकास बैंक है जो आधारभूत संरचना और सतत विकास परियोजनाओं को समर्थन देता है।

Static Part | स्थैतिक जानकारी:

- AIIB Full Form – Asian Infrastructure Investment Bank
- AIIB का पूर्ण रूप – एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक
- AIIB Established – 2016
- AIIB की स्थापना – 2016
- AIIB Headquarters – Beijing, China
- AIIB मुख्यालय – बीजिंग, चीन
- AIIB Members – 111 member states
- AIIB के सदस्य – 111 सदस्य देश
- President of AIIB – Zou Jiayi
- AIIB के अध्यक्ष – Zou Jiayi

Ques: MobiKwik recently received RBI's in-principle approval for which licence?

प्रश्न: मोबिक्विक को हाल ही में RBI से किस लाइसेंस के लिए सैद्धांतिक मंजूरी प्राप्त हुई है?

- A) Small Finance Bank Licence / स्मॉल फाइनेंस बैंक लाइसेंस
- B) Insurance Broker Licence / इंश्योरेंस ब्रोकर लाइसेंस

C) Payment Aggregator-Physical (PA-P) Licence / पेमेंट एग्रीगेटर-फिजिकल लाइसेंस

D) NBFC Licence / एनबीएफसी लाइसेंस

E) Digital Banking Licence / डिजिटल बैंकिंग लाइसेंस

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

- Fintech company MobiKwik received the Reserve Bank of India's in-principle approval for a Payment Aggregator-Physical (PA-P) licence.
- फिनटेक कंपनी मोबिक्विक को भारतीय रिजर्व बैंक से पेमेंट एग्रीगेटर-फिजिकल (PA-P) लाइसेंस के लिए सैद्धांतिक मंजूरी प्राप्त हुई।
- The licence will help MobiKwik expand its offline merchant payment infrastructure across India.
- यह लाइसेंस मोबिक्विक को भारतभर में ऑफलाइन मर्चेट पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार करने में मदद करेगा।
- The company identified small businesses, oil & gas outlets, and organised retail as key focus sectors.
- कंपनी ने छोटे व्यवसायों, तेल एवं गैस आउटलेट्स तथा संगठित रिटेल को प्रमुख फोकस क्षेत्र बताया है।
- MobiKwik aims to achieve 10x growth in its merchant business by FY28.
- मोबिक्विक का लक्ष्य FY28 तक अपने मर्चेट बिजनेस में 10 गुना वृद्धि हासिल करना है।
- Co-founder & CEO Bipin Preet Singh stated that the approval strengthens the company's ability to scale merchant payments nationwide.
- सह-संस्थापक एवं CEO बिपिन प्रीत सिंह ने कहा कि यह मंजूरी कंपनी की देशभर में मर्चेट पेमेंट सेवाओं को बढ़ाने की क्षमता को मजबूत करेगी।
- The approval is expected to strengthen digital payment infrastructure and offline payment acceptance in India.
- यह मंजूरी भारत में डिजिटल भुगतान अवसंरचना और ऑफलाइन भुगतान स्वीकृति प्रणाली को मजबूत करने में सहायक होगी।

Static Part | स्थैतिक जानकारी:

- MobiKwik Founded – 2009
- मोबिक्विक की स्थापना – 2009
- Headquarters – Gurugram, Haryana
- मुख्यालय – गुरुग्राम, हरियाणा
- Co-founder & CEO – Bipin Preet Singh
- सह-संस्थापक एवं CEO – बिपिन प्रीत सिंह
- Regulator – Reserve Bank of India (RBI)
- नियामक संस्था – भारतीय रिजर्व बैंक (RBI)

Ques: Which programme launched by SIDBI aims to modernise 10,000 rural micro and artisan enterprises over the next three years?

प्रश्न: SIDBI द्वारा शुरू किया गया कौन-सा कार्यक्रम अगले तीन वर्षों में 10,000 ग्रामीण सूक्ष्म एवं कारीगर उद्यमों के आधुनिकीकरण का लक्ष्य रखता है?

- A) Rural Growth Mission / ग्रामीण विकास मिशन
- B) MSME Udaan Programme / एमएसएमई उड़ान कार्यक्रम
- C) Gram Udyam Scheme / ग्राम उद्यम योजना
- D) Digital MSME Initiative / डिजिटल एमएसएमई पहल
- E) Modernisation of Rural Enterprises (MORE) Programme / मॉडर्नाइजेशन ऑफ रूरल एंटरप्राइजेज (MORE) कार्यक्रम

Answer: Option E

Explanation | व्याख्या:

- The Modernisation of Rural Enterprises (MORE) Programme was launched by SIDBI to modernise 10,000 rural micro and artisan enterprises over the next three years.
- SIDBI द्वारा शुरू किया गया Modernisation of Rural Enterprises (MORE)

Programme अगले तीन वर्षों में 10,000 ग्रामीण सूक्ष्म एवं कारीगर उद्यमों के आधुनिकीकरण का लक्ष्य रखता है।

- SIDBI also launched “SIDBI MachFin Mart,” a digital platform for MSMEs.
- SIDBI ने MSMEs के लिए “SIDBI MachFin Mart” नामक डिजिटल प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया।
- The platform will help MSMEs access machinery and modern technology through a structured marketplace.
- यह प्लेटफॉर्म MSMEs को संरचित मार्केटप्लेस के माध्यम से मशीनरी और आधुनिक तकनीक तक पहुँच प्रदान करेगा।
- SIDBI introduced the RRB Co-Lending Portal to support joint lending by SIDBI and Regional Rural Banks (RRBs).
- SIDBI ने SIDBI और Regional Rural Banks (RRBs) द्वारा संयुक्त ऋण सुविधा के लिए RRB Co-Lending Portal भी शुरू किया।
- The portal will help provide loans to MSMEs in rural and underserved areas.
- यह पोर्टल ग्रामीण एवं वंचित क्षेत्रों के MSMEs को ऋण उपलब्ध कराने में सहायता करेगा।
- These initiatives were announced during SIDBI’s 37th Foundation Day celebration held in Mumbai.
- इन पहलों की घोषणा मुंबई में आयोजित SIDBI के 37वें स्थापना दिवस समारोह के दौरान की गई।

Static Part | स्थैतिक जानकारी:

- SIDBI Full Form – Small Industries Development Bank of India
- SIDBI का पूर्ण रूप – भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक
- SIDBI Established – 2 April 1990
- SIDBI की स्थापना – 2 अप्रैल 1990
- SIDBI Headquarters – Lucknow, Uttar Pradesh
- SIDBI मुख्यालय – लखनऊ, उत्तर प्रदेश
- Chairman & Managing Director of SIDBI – Manoj Mittal
- SIDBI के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक – मनोज मित्तल

Ques: The newly launched LIC plans “New Jeevan Sathi” are mainly designed for whom?

प्रश्न: LIC द्वारा लॉन्च की गई “New Jeevan Sathi” योजनाएँ मुख्य रूप से किनके लिए बनाई गई हैं?

- A) Senior Citizens / वरिष्ठ नागरिक
- B) Students / छात्र
- C) Married Couples / विवाहित दंपति
- D) Farmers / किसान
- E) Government Employees / सरकारी कर्मचारी

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

- Life Insurance Corporation of India (LIC) launched two new joint life insurance plans.
- भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) ने दो नई संयुक्त जीवन बीमा योजनाएँ शुरू कीं।
- The two plans are New Jeevan Sathi Single Premium (Plan 888) and New Jeevan Sathi Limited Premium (Plan 889).
- ये दो योजनाएँ New Jeevan Sathi Single Premium (Plan 888) और New Jeevan Sathi Limited Premium (Plan 889) हैं।
- Both plans are joint life savings and protection products designed for married couples.
- दोनों योजनाएँ विवाहित दंपतियों के लिए संयुक्त जीवन बचत और सुरक्षा उत्पाद हैं।
- The policies cover a married individual and his/her spouse under a single policy.
- ये योजनाएँ एक ही पॉलिसी के अंतर्गत पति-पत्नी दोनों को कवर करती हैं।
- The minimum basic sum assured under both plans is ₹3 lakh.
- दोनों योजनाओं में न्यूनतम मूल बीमित राशि ₹3 लाख है।
- The minimum entry age for purchasing the plans is 18 years.
- इन योजनाओं को खरीदने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है।
- Both policies provide guaranteed additions that increase maturity or death benefits.

• दोनों योजनाएँ गारंटीड एडिशन प्रदान करती हैं, जिससे मैच्योरिटी या मृत्यु लाभ बढ़ता है।

- The plans became available for purchase from 1 June 2026.
- ये योजनाएँ 1 जून 2026 से खरीद के लिए उपलब्ध हो गईं।
- LIC CEO & MD Siddhartha Mohanty launched the new policies.
- LIC के CEO एवं MD सिद्धार्थ मोहंती ने नई योजनाओं को लॉन्च किया।

Static Part | स्थैतिक जानकारी:

- LIC Established – 1 September 1956
- एलआईसी की स्थापना – 1 सितंबर 1956
- LIC Headquarters – Mumbai
- एलआईसी मुख्यालय – मुंबई
- LIC Motto – “Yogakshemam Vahamyaham”
- एलआईसी का आदर्श वाक्य – “योगक्षेमं वहाम्यहम्”
- Insurance Regulatory Body – IRDAI
- बीमा नियामक संस्था – IRDAI

Ques: According to the RBI's new clarification, after completing 10 years of continuous service, a director of a co-operative bank can be reappointed to the same board only after what period?

प्रश्न: RBI के नए स्पष्टीकरण के अनुसार, सहकारी बैंक के निदेशक के रूप में लगातार 10 वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद, उसी बोर्ड में पुनर्नियुक्ति कितने समय बाद हो सकती है?

- A) 1 year / 1 वर्ष
- B) 2 years / 2 वर्ष
- C) 3 years / 3 वर्ष
- D) 5 years / 5 वर्ष
- E) 10 years / 10 वर्ष

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

- The Reserve Bank of India (RBI) stated that a director on the board of co-operative banks who has served continuously for 10 years can be reappointed only after a three-year cooling-off period.
- भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने कहा कि सहकारी बैंक के बोर्ड में लगातार 10 वर्ष तक सेवा देने वाला निदेशक केवल तीन वर्ष की कूलिंग-ऑफ अवधि के बाद ही पुनर्नियुक्त हो सकता है।
- During the cooling-off period, the individual cannot be associated with the same bank in any capacity except as a regular member or customer.
- कूलिंग-ऑफ अवधि के दौरान संबंधित व्यक्ति उसी बैंक से किसी भी रूप में जुड़ा नहीं रह सकता, सिवाय सामान्य सदस्य या ग्राहक के रूप में।
- However, such individuals can become directors on the board of another co-operative bank during this period.
- हालांकि, इस अवधि में वे किसी अन्य सहकारी बैंक के बोर्ड में निदेशक बन सकते हैं।
- RBI clarified that while calculating continuous tenure, service in Urban Co-operative Banks (UCBs), State Co-operative Banks, and Central Co-operative Banks will be counted together.
- RBI ने स्पष्ट किया कि निरंतर कार्यकाल की गणना करते समय Urban Co-operative Banks (UCBs), State Co-operative Banks तथा Central Co-operative Banks में दी गई सेवा को एक साथ जोड़ा जाएगा।
- Periods of service separated by breaks of less than three years will also be counted together.
- तीन वर्ष से कम के अंतराल से अलग हुई सेवाओं को भी एक साथ गिना जाएगा।
- The proposal is in line with the Banking Regulation (Amendment) Act.
- यह प्रस्ताव Banking Regulation (Amendment) Act के अनुरूप है।
- The Act increased the maximum continuous tenure for directors of co-operative banks from eight years to ten years.
- इस अधिनियम के तहत सहकारी बैंकों के निदेशकों की अधिकतम निरंतर सेवा अवधि को 8 वर्ष से बढ़ाकर 10 वर्ष किया गया है।

Ques: Under the CGSMFI 2.0 scheme, the NCGTC has raised the individual loan limit for large Microfinance Institutions (MFIs) to how much amount?

प्रश्न: CGSMFI 2.0 योजना के तहत, NCGTC ने बड़े माइक्रोफाइनेंस संस्थानों (MFIs) के लिए व्यक्तिगत ऋण सीमा को बढ़ाकर कितनी राशि कर दिया है?

- A) ₹500 crore / ₹500 करोड़
- B) ₹750 crore / ₹750 करोड़
- C) ₹1,000 crore / ₹1,000 करोड़
- D) ₹1,500 crore / ₹1,500 करोड़
- E) ₹2,000 crore / ₹2,000 करोड़

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

- The National Credit Guarantee Trustee Company Ltd (NCGTC) has revised the loan limit for large Microfinance Institutions (MFIs) from ₹300 crore to ₹1,000 crore under CGSMFI 2.0.
- नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (NCGTC) ने CGSMFI 2.0 के तहत बड़े माइक्रोफाइनेंस संस्थानों (MFIs) के लिए ऋण सीमा को ₹300 करोड़ से बढ़ाकर ₹1,000 करोड़ कर दिया है।
- Large MFIs are defined as institutions having Assets Under Management (AUM) of ₹2,000 crore and above.
- बड़े एमएफआई वे संस्थान हैं जिनकी प्रबंधन के तहत संपत्ति (AUM) ₹2,000 करोड़ या उससे अधिक है।
- The revised loan amount is subject to a ceiling of 20% of the institution's AUM.
- संशोधित ऋण राशि संबंधित संस्थान के AUM के अधिकतम 20% तक सीमित रहेगी।
- The Credit Guarantee Scheme for Microfinance Institutions 2.0 (CGSMFI 2.0) came into effect on 20 March 2026.
- माइक्रोफाइनेंस संस्थानों के लिए क्रेडिट गारंटी योजना 2.0 (CGSMFI 2.0) 20 मार्च 2026 से लागू हुई।
- The overall guarantee issuance under the scheme has been capped at

₹20,000 crore.

- इस योजना के तहत कुल गारंटी जारी करने की सीमा ₹20,000 करोड़ निर्धारित की गई है।

- Lenders are required to allocate at least 5% of the total loan amount to small MFIs and 10% to medium-sized MFIs.

- ऋणदाताओं को कुल ऋण राशि का कम से कम 5% छोटे एमएफआई और 10% मध्यम आकार के एमएफआई को देना अनिवार्य है।

- The maximum tenure of loans under the scheme is 3 years, including a 1-year moratorium and 2 years repayment period.

- योजना के तहत ऋण की अधिकतम अवधि 3 वर्ष है, जिसमें 1 वर्ष का मोराटोरियम और 2 वर्ष की पुनर्भुगतान अवधि शामिल है।

Static Part | स्थैतिक जानकारी:

- NCGTC Ownership – Wholly owned by Government of India

- NCGTC स्वामित्व – पूर्णतः भारत सरकार के स्वामित्व में

- CGSMFI Full Form – Credit Guarantee Scheme for Microfinance Institutions

- CGSMFI का पूर्ण रूप – Credit Guarantee Scheme for Microfinance Institutions

- MFI Full Form – Microfinance Institution

- MFI का पूर्ण रूप – माइक्रोफाइनेंस इंस्टीट्यूशन

- AUM Full Form – Assets Under Management

- AUM का पूर्ण रूप – एसेट्स अंडर मैनेजमेंट

EXAM
Genius